1037. [*Transferred to the 29th July, 1992*].

Judges of Supreme Court and High Court appointed to various Commissions

1038. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state the number of Judges of High Courts and Supreme Court among the sitting as well as retired who have been appointed to various Commissions of Enquiry State-wise during the last five years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना

1039. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना किए जाने की काफी पुरानी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा गठित जसवंत सिंह समिति ने भी यह सिफारिश की है कि वहां उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ की स्थापना की जानी चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो उसके कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना की मांग, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही के लिए, बहुत समय से चली आ रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) जसवंत सिंह आयोग की विनिदिष्ट सिफारिशें, अक्टूबर, 1986 में, उत्तर प्रदेश सरकार को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार के विचार प्राप्त करने के लिए भेज दी गई थी। राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशों के अनुसार उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कोई विनिदिष्ट, निश्चित प्रस्ताव नहीं भेजा है।

Vacant posts of judges in the Delhi High Court

1040. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain posts of judges in the Delhi High Court have been falling vacant since long;

(b) if so, whether Government will take immediate action in public interest for filling up of these posts within a month; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) As on date there are 6 vacancies of permanent/Additional Judges in Delhi High Court in its sanctioned strength of 30 permanent/Additional Judges. One vacancy arose on 3.9.91 and 3 vacancies on 22.1.92. Again, one vacancy arose on 10.4.92 and remaining one on 8.5.92. Recommendations for filling up these vacancies have been received and further consultation in terms of article 217 of the Constitution is on. While all possible efforts are being made to fill up the vacancies at the earliest, it is not possible to indicate by when the vacancies would be filled up.